

‘जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं’

तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह भी कहा, अब उनका पूरा फोकस पार्टी के नव निर्माण पर है

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 17 मई। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, क्योंकि अब उनका ध्यान पार्टी को पुनः बनाने पर है।

हालिया चुनाव में टीएमसी के हारने के बाद, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने उन उम्मीदवारों से अपील की, जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव लड़ा था, कि वे संगठन को पुनर्निर्मित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उन्हें जाने की पूरी स्वतंत्रता है।

शुक्रवार को कालीघाट स्थित अपने निवास पर तृणमूल कांग्रेस के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ

- ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव लड़ चुके सभी पार्टी प्रत्याशियों से संगठन को मजबूत बनाने का आग्रह किया
- अपने कालीघाट आवास पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं से कहा, जिन पार्टी कार्यलयों को तोड़ा गया, उनकी मरम्मत करें, मैं खुद भी उनमें पेंट करूंगी। तृणमूल झुकती नहीं।

बैठक में, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी उपस्थित थे, ममता ने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव में भारी हार का सामना करने के बावजूद, संगठन फिर उठ खड़ा होगा।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा, “जो लोग अन्य पार्टियों में जा रहे

हैं, उन्हें जाने दो। मैं पार्टी को नई ताकत के साथ पुनर्निर्मित करूंगी। जो रुक रहे हैं, उनसे कहती हूँ कि क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यलयों को पुनः बनाएँ, पेंट करें और फिर से खोलें। जरूरत पड़े तो मैं भी उन्हें पेंट करूंगी। तृणमूल कांग्रेस कभी झुकती नहीं। जनता का जनदेश लूटा गया है।

ये टिप्पणियाँ उस समय आईं, जब टीएमसी को चुनाव नतीजों में नाटकीय उलटफेर के बाद राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी से विपक्ष की बेंच पर स्थानांतरित होना पड़ा।

राज्य की 294 विधानसभा सीटों में पार्टी केवल 80 सीटें जीत पाई।

ममता बनर्जी स्वयं भवानीपुर से हार गईं, जिसे लंबे समय से उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है।

टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि दार्जिलिंग हिल्स की तीन सीटें अपने सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) को दी थीं, जिसके नेता अमित थापा हैं। इनमें केवल 80 उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि 211 हारे, जिनमें कई दिग्गज नेता और मंत्री भी शामिल हैं।

गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी ने श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था

नई दिल्ली, 17 मई। जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने के इरादे से घुसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक पाकिस्तानी आतंकी को लेकर चौकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आतंकी ने अपने मिशन के बीच न केवल गतिविधियाँ जारी रखीं, बल्कि उसने

- लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद उस्मान जट का काम जम्मू-कश्मीर में आतंकी स्लीपर सेल तैयार करना था।

श्रीनगर में हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया। मोहम्मद उस्मान जट, जिसे आतंकी नेटवर्क में ‘चीनी’ के नाम से जाना जाता है, को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। वह पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षित सदस्य बताया जा रहा है।

जांच में सामने आया है कि कश्मीर में घुसपैठ के बाद उसे वहां की जिंदगी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रविवार को यूएई के एकमात्र परमाणु प्लांट पर ड्रोन हमला

हमले में किसी के हताहत होने तथा किसी भी प्रकार के रेडियोधर्मी रिसाव से साफ इनकार

दुबई, 17 मई। संयुक्त अरब अमीरात के बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रविवार को एक ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। इस हमले के कारण संयंत्र की बाहरी सीमा पर स्थित एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। इस घटना ने ईरान युद्ध में चल रहे अस्थिर संघर्ष विराम को एक बार फिर खतरे में डाल दिया है।

अबू धाबी के अधिकारियों ने बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। हालाँकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके साथ ही, किसी भी प्रकार के रेडियोधर्मी रिसाव की बात से भी साफ इनकार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस हमले का सीधा शक ईरान पर गहरा गया है। ईरान पिछले कुछ दिनों

- 20 अरब डॉलर की लागत से वर्ष 2020 में बना बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई की एक-चौथाई बिजली जरूरतों को पूरा करता है।
- हमले की जिम्मेदारी किसी राष्ट्र/संगठन ने नहीं ली है, लेकिन सीधा शक ईरान पर जा रहा है।

यूएई के परमाणु नियामक ने कहा कि इस आग से संयंत्र की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। नियामक संस्था ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी इकाइयाँ हमला की तरह सामान्य रूप से काम कर रही हैं। यूएई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रणालियों और सैनिकों की मेजबानी की थी, जिससे ईरान बेहद नाराज है। दक्षिण कोरिया की मदद से निर्मित 20 अरब डॉलर का बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र साल 2020 में चालू हुआ था। यह अरब प्रायद्वीप का पहला और एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र यूएई की कुल बिजली जरूरतों का एक-चौथाई हिस्सा पूरा करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही, यह अरब दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है।

यूएई के परमाणु नियामक ने कहा कि इस आग से संयंत्र की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है। नियामक संस्था ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी इकाइयाँ हमला की तरह सामान्य रूप से काम कर रही हैं। यूएई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में गर्मी बढ़ी, बाड़मेर 45.4 डिग्री पहुँचा

मौसम विभाग को आने वाले दिनों में राज्य का तापमान 44 से 46 डिग्री पहुँचने की आशंका

जयपुर, 17 मई। राजस्थान में एक बार फिर गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के सात शहरों का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि आठ शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कई क्षेत्रों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग के अनुसार, बाड़मेर 45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि संगरिया में न्यूनतम तापमान 33.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सबसे गर्म रात रही। इसके अलावा, बीकानेर में 45 डिग्री, जैसलमेर में 44.9 डिग्री तथा वनस्थली, चित्तौड़गढ़, फलौदी और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। रात के तापमान की बात करें तो संगरिया के अलावा, जालौर, फलौदी, बाड़मेर, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के

- राज्य में सात शहरों का तापमान 44 डिग्री से अधिक रहा। ये शहर हैं, बाड़मेर, संगरिया, बीकानेर, जैसलमेर, वनस्थली, चित्तौड़गढ़, फलौदी व श्रीगंगानगर। जयपुर में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री रहा।

निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। आगामी दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री और बढ़ती होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुँच सकता है और

सुप्रीम कोर्ट में 38 जज होंगे

नई दिल्ली, 17 मई। देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक नया अध्यादेश जारी

कहीं-कहीं हीटवेव चल सकती है। उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रहने और कुछ क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में 18 से 22 मई के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज सतही हवाएँ चलने का अनुमान है।

गोधेनबर्ग शहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। यह मोदी को मिलने वाला 31वाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन पहुँचे

नई दिल्ली, 17 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी पाँच देशों की छह दिवसीय विदेश यात्रा के तीसरे दिन रविवार को नोर्डलैंड से स्वीडन पहुँचे। प्रधानमंत्री मोदी का विमान जैसे ही स्वीडन की सीमा में पहुँचा था, स्वीडिश फाइटर जेट्स ने उसे सुरक्षा देते हुए एस्कॉर्ट किया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन पीएम मोदी को रिसीव

- वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से मुलाकात करेंगे।

करने गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर पहुँचे थे। वहीं पीएम मोदी को स्वीडन में ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलेर स्टार कमांडर ग्रेड क्रॉस’ सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह किसी भी देश के प्रधानमंत्री या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है।

गोधेनबर्ग शहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन समेत कई सीनियर नेता मौजूद रहे। यह मोदी को मिलने वाला 31वाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में आज एक लाख लोग शामिल होंगे

तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले समारोह में पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है

नई दिल्ली, 17 मई। सतीशन दामोदर मेनन वडस्सेरी (वीडी सतीशन) सोमवार को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। इससे पहले वर्ष 2011-2016 तक कांग्रेस के ओमन चांडी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

राजधानी तिरुवनंतपुरम में समारोह की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। वीडि सतीशन के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। सतीशन ने प्रस्तावित 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल तैयार कर लिया है। इसमें पाँच मंत्री मंत्रिमंडल शपथ ले लेंगे। तीन महिलाएं भी शामिल की गई हैं। सतीशन ने रविवार को राज्यपाल राजेंद्र अल्लेंकर से मुलाकात कर मंत्रियों की सूची सौंपी।

इन मंत्रियों में रमेश चेन्नितला, केरल प्रदेश कांग्रेस समिति

- केरलम में कांग्रेस की सरकार दस साल बाद बनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा कर्नाटक व तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।

(केपीसीसी) प्रमुख सनी जोसेफ और के मुरलीधरन शामिल हैं। सतीशन ने कहा कि तिरुवंचूर राधाकृष्णन विधानसभा अध्यक्ष होंगे और शनिमोल उस्मान उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) केरल कांग्रेस के पीजे जोसेफ होंगे।

शपथ ग्रहण समारोह में करीब एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस इसे एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्ढा के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कर्नाटक

और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी समारोह में मौजूद रहेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले लगभग दस दिनों से दिल्ली और केरल में लगातार राजनीतिक मंथन चल रहा था। अंततः कांग्रेस आलाकमान ने वीडि सतीशन के नाम पर सहमति बनाई। निर्णायक दौर तब शुरू हुआ, जब केसी वेणुगोपाल को दिल्ली स्थित राहुल गांधी के आवास पर बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार, करीब तीन घंटे चली बैठक में राहुल गांधी ने उन्हें नेतृत्व के अंतिम फैसले की जानकारी दी और सतीशन के नाम पर मुहर लगाई।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, वीडि सतीशन की साफ-

सुधरी छवि, प्रभावशाली वक्तृत्व शैली और मजबूत संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें राज्य की राजनीति में अलग पहचान दिलाई है। विपक्ष के नेता के रूप में भी उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेर और जनता के बीच सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी। यही कारण है कि उन्हें एक जमीनी और प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता है।

राजनीति के जानकारों का मानना है कि नई सरकार के शुरूआती सौ दिनों बेहद अहम होंगे। इसी दौरान सरकार की प्रशासनिक क्षमता, निर्णय लेने की शैली और जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा स्पष्ट होगी।

सीएनजी की कीमत एक रुपया और बढ़ी

नई दिल्ली, 17 मई। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमतों में तीन दिनों के भीतर दूसरी बार बढ़ोत्तरी की गई है। नई दरें रविवार

- एनसीआर क्षेत्र में तीन दिनों में दूसरी बार सीएनजी की दर बढ़ी है।

से लागू हो गई है। ताजा बढ़ोत्तरी के बाद, दिल्ली में सीएनजी एक रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है।

इससे पहले 15 मई को गैस कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों में दो रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की थी। लगातार दूसरी बढ़ोत्तरी के साथ तीन दिनों में सीएनजी कुल तीन रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत बढ़ कर 88.70 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं, मुंबई में सीएनजी लगभग 84 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तीन रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई थी।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए वाइस चांसलर और डीन को दी गई जिम्मेदारियों पर रोक

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाई

जयपुर, 17 मई (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव को लेकर एकलपीठ द्वारा दिए गए कई निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाई है। न्यायाधीश सुदेश बंसल और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

इस मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पैरवी के लिए पेश हुए थे। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने 12 दिसंबर 2025 को अपने आदेश में कहा था कि, विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव करवाना, विद्यार्थियों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बढ़ाने तथा सामाजिक दायित्व से रूबरू करवाने में महत्वपूर्ण

है। चुनाव की प्रक्रिया यह विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के साथ, “हाथ से हाथ मिलाकर” चलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया तथा लोकतंत्र के प्रति जागरूकता भी शिक्षा का ही हिस्सा है। एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की थी कि चूँकि केवल 5 ही छात्र चुनाव कराने के लिए अदालत के समक्ष आए हैं, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि प्रदेश में लाखों छात्रों के हित को देखते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि छात्रसंघ चुनाव करवाना संवैधानिक अधिकार नहीं है, परंतु एक विधिक अधिकार है, जिसे लागू करवाने के लिए छात्र यूनिवर्सिटी के उच्चस्तरीय अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

- अदालत ने कहा कि एक तरफ तो एकलपीठ ने छात्रसंघ चुनाव करवाने की गुहार को अस्वीकार किया है, परंतु दूसरी ओर याचिका में की गई गुहार और मांगों से बढ़कर अन्य निर्देश दे दिए हैं, जिन पर अंतरिम रोक रहेगी।
- ज्ञात रहे कि एकलपीठ ने अपने आदेश में 19 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे तक समय निर्धारित करते हुए आपत्ति सुनने तथा 15 दिन के भीतर उन पर निर्णय करने के निर्देश दिए थे।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने एकलपीठ को तर्क दिया था कि, प्रदेश में 28 राज्यपोषित विश्वविद्यालय, 53 निजी यूनिवर्सिटी तथा 596 सरकारी कॉलेज हैं। अकेले राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर में ही 26500 विद्यार्थी

अध्ययनरत हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की पालना करना कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 6-8 सप्ताह के बीच छात्रसंघ चुनाव करवाना अनौपचारिक ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित करने जैसा है।

न्यायाधीश समीर जैन ने सभी तर्कों को रिक्त पर लिया था, जिसके बाद छात्रसंघ चुनाव करवाने की गुहार को अस्वीकार करवाते ही नतीजा दे दिया था, परंतु यह निर्देश दिए थे कि छात्र सीधे अदालतों का दरवाजा न खटखटाएँ, उससे पूर्व कॉलेज व यूनिवर्सिटी में उपयुक्त आधारभूत ढांचा हो तथा जहाँ चुनाव करवाने को लेकर दायर शिकायतों का निस्तारण हो सके, वहाँ जायें। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट वेलफेयर डीन, विश्वविद्यालय की चुनाव कमेटी अथवा शिकायत निस्तारण समिति भी विद्यार्थियों की मांगों पर सुनवाई करें। अदालत ने अपने आदेश में 19 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे तक समय निर्धारित करते हुए आपत्ति सुनने तथा 15 दिन के भीतर उन पर निर्णय करने के निर्देश दिए थे।

साथ ही यह भी कहा था कि डीन अथवा उपकुलपति के स्तर पर होने वाले इस निर्णय से कॉलेजों व संबंधित पक्षकारों को अवगत कराया जाए। एकलपीठ ने कहा था कि, ये निर्देश इस उद्देश्य से दिए जा रहे हैं, ताकि छात्रसंघ चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही भविष्य में इसकी पालना सुनिश्चित हो। इस पूरे प्रकरण में हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुदेश बंसल और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। खंडपीठ ने कहा है कि एक तरफ एकलपीठ ने छात्रसंघ चुनाव करवाने की गुहार को अस्वीकार किया है, परंतु दूसरी ओर जनहित याचिका में की गई गुहार और मांगों से बढ़कर अन्य निर्देश दे दिए हैं, जिन पर अंतरिम रोक रहेगी।